www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 2 अगस्त 2019

दैनिक जागरण
प्रत्येक समस्या अपना समाधान लेकर ही उत्पन्न होती है

मंदी का अंदेशा

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की ओर से विकास दर का अनुमान घटाने पर हैरानी इसलिए नहीं, क्योंकि बीते कुछ समय से लगातार ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सब कुछ ठीक नहीं। बात चाहे मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में चार वर्षों की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज होने की हो या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी के हालात की अथवा शेयर बाजार में छाई सुस्ती की, चारों ओर से उभरते विपरीत संकेत कारोबार जगत को हतोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। इन नकारात्मक संकेतों के बीच मोदी सरकार इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकती कि कैफे कॉफी डे के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ की आत्महत्या ने भी आर्थिक माहौल में निराशा घोलने का काम किया है। भले ही सिद्धार्थ की आत्महत्या के मूल कारण कुछ और हों, लेकिन उनकी मौत को जिस तरह प्रतिकूल कारोबारी माहौल से जोड़ा जा रहा है उससे नीति-नियंता अनजान नहीं हो सकते। नीति-नियंताओं को इस बात से भी अवगत होना चाहिए कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट उद्योग-व्यापार जगत को उत्साह प्रदान करने में सहायक नहीं साबित हुआ। सच तो यह है कि आम बजट के कुछ प्रावधानों ने कारोबार जगत को हतोत्साहित करने का काम किया है।

इससे इन्कार नहीं कि सरकार के विभिन्न विभाग कारोबारी माहौल ठीक करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वे कामयाब होते हुए भी दिख रहे हैं? इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर कारोबार जगत की चिंताओं का समाधान करने की पहल सरकार के शीर्ष स्तर पर क्यों नहीं हो रही है? क्या यह सही समय नहीं कि वित्त मंत्री या फिर खुद प्रधानमंत्री आगे आकर उद्योग-व्यापार जगत को इसके लिए आश्वस्त करें कि उसकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा? इस तरह का कोई आश्वासन देना इसलिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है, क्योंकि उद्योग-व्यापार को गति प्रदान करके ही सरकार जनकल्याण और विकास की अपनी योजनाओं पर अमल कर पाएगी। निःसंदेह गरीब, किसान और अन्य वंचित तबकों का उत्थान सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए, लेकिन इस तरह की प्राथमिकताएं तो तभी पूरी हो पाएंगी जब अर्थव्यवस्था की सुस्ती दूर करने में कामयाबी मिलेगी। यह कामयाबी कारोबारियों को भरोसा दिलाने और उनके मनोबल को बढ़ाने से ही मिलेगी। यह शुभ संकेत नहीं कि अर्थव्यवस्था के मंदी के चपेट में आने का अंदेशा उभर आया है। इसके पहले कि मंदी की आशंका और गहराए, मोदी सरकार को हालात ठीक करने के लिए न केवल सक्रिय होना चाहिए, बल्कि इसकी चिंता करते हुए दिखना भी चाहिए कि कारोबार जगत की समस्याओं का तेजी से निदान करना उसकी प्राथमिकता में है।

ममता की कोशिश

तृणमूल कांग्रेस के लिए 2021 का पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव काफी अहम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा ने तृणमूल से 14 सीटें छीन ली है उसके बाद से तृणमूल प्रमुख एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चिंता बढ़ना लाजिमी है। इसीलिए उन्होंने पहली बार भाजपा एवं अन्य दलों की तरह चुनावी रणनीतिकार का सहारा लिया है। उनकी चुनावी रणनीति इन दिनों प्रशांत किशोर संभाल रहे हैं और उनकी रणनीति के तहत ममता ने भी कोशिश शुरू कर दी है। राज्य की जनता में तृणमूल के प्रति भरोसा बढ़ाने के लिए 'दीदी के बोलो' अभियान शुरू किया गया है। तृणमूल नेतृत्व और किशोर की 'इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी' (आइ-पीएसी) के अधिकारियों ने हालांकि फोन पर हुई बातचीत या किन लोगों ने फोन किया, इस संबंध में कोई जानकारी साझा नहीं की, परंतु बुधवार को बताया गया कि सोमवार को डिजिटल मंच के शुरू होने के बाद से अब तक इस पर दो लाख से अधिक फोन कॉल आ चुके हैं। वहीं कम से कम एक लाख लोगों ने हेल्पलाइन नंबर तथा वेबसाइट पर अपनी राय रखी है और समस्याएं बताई हैं। व्यापक प्रतिक्रिया मिलने की बातें कही जा रही हैं। लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद ममता ने जनता तक पहुंचने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत पार्टी के एक हजार नेता अगले 100 दिनों में 10 हजार गांवों की यात्रा करेंगे और जनता की समस्याओं को समझकर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। यह अभियान भी प्रशांत किशोर की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। राज्य में भाजपा की अचानक बढ़ी लोकप्रियता तृणमूल के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। वाम दलों के 34 वर्षों के शासन को समाप्त करते हुए 2011 में सुश्री बनर्जी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर राज्य में अपनी सरकार बनाई थी, परंतु पिछले पांच वर्षों में भाजपा की शक्ति बंगाल में काफी बढ़ चुकी है जिसके मद्देनजर उन्होंने अभी से ही चुनावी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि तृणमूल को पता है कि पारंपरिक राजनीति के जरिए भाजपा से पार पाना संभव नहीं है। इसीलिए आधुनिक राजनीतिक सोच एवं चुनाव प्रबंधन में माहिर प्रशांत किशोर को साथ लेकर ममता भाजपा को 2021 में जमीन चटाने की कोशिश में हैं।

अपनी अफगान नीति को धार दे भारत

ब्रिगेडियर आरपी सिंह

काबुल में संभावित तालिबानी शासन इस्लामाबाद को भारत के खिलाफ सामरिक पैठ बनाने में फायदा ही पहुंचाएगा

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान कतर एयरलाइंस की व्यावसायिक उड़ान से जब अमेरिका पहुंचे तो उनकी आगवानी के लिए कोई अमेरिकी मंत्री मौजूद नहीं था। उनके वित्त मंत्री शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तानी राजदूत के अलावा पाकिस्तान मूल के कुछ अमेरिकियों ने ही उनका स्वागत किया। वहां केवल एक अमेरिकी महिला प्रोटोकॉल अधिकारी ही उपस्थित थीं। उन्हें तब और असहज होना पड़ा जब पाकिस्तान के बलूच, सिंधी और मोहाजिर तबके के लोगों ने उनके सामने विरोध-प्रदर्शन किया। इमरान खान के साथ पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जावेद बाजवा के अलावा ताकतवर खुफिया एजेंसी आइएसआइ के मुखिया लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी गए। ये सभी हवाई अड्डे से मेट्रो रेल के जरिये पाकिस्तानी दूतावास पहुंचे। ये सभी दूतावास में ही रहे। उनके द्वारा बरती गई इस किफायत की कंगाल और बदहाल होते देश में लोगों द्वारा भारी सराहना की गई। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ सेना के दो शीर्ष जनरल भी साथ गए। असल में इमरान अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान से संपर्क साधना चाहते थे और दोनों जनरल अमेरिकी सेना के साथ मिलकर अफगानिस्तान में काम कर चुके थे। पाकिस्तानी जनरल अमेरिका के शीर्ष सैन्य कमांडरों को यह समझाने में सफल रहे कि अपनी धरती पर आतंक के खिलाफ मुहिम में पाकिस्तान खासा गंभीर है। दूसरी वजह यह रही कि व्हाइट हाउस में अपने सैन्य नेतृत्व की परेड कराकर इमरान खान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बात के लिए आश्वस्त करने की कोशिश की कि जो भी वादे किए जाएंगे उन्हें पूरा किया जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के वास्तविक शासकों यानी सैन्य कमांडरों के सामने हो रहे हैं।

डोनाल्ड ट्रंप-इमरान खान वार्ता की कड़ी सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने जोड़ी थी जिन्होंने इसके लिए ट्रंप के दामाद के साथ अपने निजी रिश्तों का सहारा लिया। इसकी कोशिशें दिसंबर, 2018 से ही शुरू हो गई थीं जब ट्रंप ने इमरान खान को पत्र लिखकर अफगान शांति प्रक्रिया में उनसे मदद मांगी थी। इमरान खान भी ट्रंप से मिलने को आतुर थे ताकि पाकिस्तान को लेकर उनकी नकारात्मक धारणा दूर कर सकें। इस्लामाबाद ने इसके लिए हालैंड एंड नाइट जैसी लाबिंग फर्म की सेवाएं ली थीं। कुछ अरसा पहले ट्रंप ने ट्विटर पर कहा था कि बीते 15 वर्षों में पाकिस्तान ने 33 अरब डॉलर की मदद के बदले में झूठ और फरेब के बदले कुछ और नहीं दिया। वही ट्रंप अब पाक के साथ संबंधों में सुधार के मकसद से इमरान खान का स्वागत करते दिखे। ट्रंप को उम्मीद है कि इमरान खान तालिबान से समझौता कराने में मददगार होंगे ताकि नवंबर, 2020 को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिकी सैनिक स्वदेश लौट आएं। इमरान खान से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने अपने चिरपरिचित अंदाज में शिगूफा छेड़ा कि पीएम मोदी ने उनसे कश्मीर में मध्यस्थता का अनुरोध किया है। इससे इमरान के मुर्झाए चेहरे पर भी मुस्कान तैरना स्वाभाविक था।

अवधेश राजपूत

अमेरिका ने इमरान खान से किसी सैन्य या आर्थिक सहायता का वादा नहीं किया है। इस दौरान पाकिस्तान को केवल 16.5 करोड़ डॉलर की राशि मिली वह भी उन एफ-16 विमानों की मरम्मत और रखरखाव के लिए जो उसे अमेरिका से मिलेंगे। इसमें भी एक शर्त यह है कि उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हालांकि इमरान खान के अमेरिका दौरे के कुछ खास निहितार्थ भी रहे। एक तो यही कि अमेरिका-पाक रिश्ते वापस सुधार की ओर अग्रसर हुए हैं। दूसरा यही कि भारत अभी भी अमेरिका के लिए अहम बना रहेगा, लेकिन वाशिंगटन इस्लामाबाद से भी संतुलन साधेगा जैसा कि वह पहले करता था। तीसरा यह कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के मामले में पाकिस्तान आधार बिंदु बन गया है। ऐसा इस्लामाबाद की संदिग्ध नीति के कारण हुआ है जहां वह तालिबान की मदद करता तो दूसरी ओर उससे लड़ने के नाम पर अमेरिका से डॉलर वसूलता रहा। यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि पाक की तालिबान पर पूरी पकड़ है। कश्मीर पर ट्रंप की शिगूफेबाजी इमरान के दौरे की सबसे बड़ी थाती रही, लेकिन इससे पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं होने वाला। कश्मीर के मसले पर अमेरिकी मध्यस्थता की संभावनाओं पर पाकिस्तानी मीडिया गदगद हो गया। ट्रंप के बयान पर भारत में विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी से निजी स्पष्टीकरण की मांग पर अड़ा, लेकिन मोदी ने बड़बोले अमेरिकी राष्ट्रपति को शर्मसार करना उचित नहीं समझा। इसे अमेरिका ने भी समझा होगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ अपनी पहली बैठक में इमरान खान ने द्विपक्षीय रिश्तों में आए खालीपन को भरने के साथ ही अविश्वास की खाई को पाटने का काम किया। इमरान का अमेरिका दौरा इसलिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह तब हुआ जब तालिबान के साथ अमेरिका की वार्ता निर्णायक दौर में पहुंच रही है। दोहा में तालिबान के साथ अगले दौर की वार्ता फिर से होने जा रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही कोई समझौता हो सकता है।

अमेरिका में इमरान खान ने स्वीकार किया कि पाकिस्तानी धरती पर करीब 40 आतंकी संगठनों के 40,000 आतंकवादी सक्रिय हैं जिन पर कार्रवाई करनी होगी। हालांकि इमरान खान के पूर्ववर्तियों ने भी ऐसे दावों के साथ पहले भी अमेरिका को गुमराह किया है और इस मामले में वक्त उनकी भी परीक्षा लेगा। इमरान खान ने अमेरिका में यह भी कहा कि वह तालिबान से मिलकर उसे अफगान सरकार से बातचीत के लिए मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस पर तालिबान के प्रवक्ता ने भी कहा कि अगर पाकिस्तान आमंत्रित करता है तो हम वहां जरूर जाएंगे।

भारत को भी अपनी अफगानिस्तान नीति में बदलाव करते हुए तालिबान से बातचीत करनी चाहिए। कूटनीतिक तकाजा यही कहता है कि व्यावहारिकता को सिद्धांतों पर तरजीह दी जाए। तालिबान भले ही आतंकी हों, लेकिन वे हैं तो अफगानी ही। मौजूदा अफगान वार्ता में शामिल न होकर भारत ने इस्लामाबाद को बढ़त बनाने का अवसर दे दिया है। अफगान तालिबान के साथ हालिया वार्ता में अमेरिका, रूस और चीन के अलावा पाकिस्तान भी शामिल हुआ। अफगानिस्तान रणनीतिक रूप से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस युद्ध पीड़ित देश में हमने मानव और अन्य संसाधनों में भारी निवेश किया है। भारत को लेकर अफगानियों में सदियों से अच्छी भावनाएं रही हैं। इनमें तालिबान के कुछ धड़े भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति से भी ये भावनाएं बढ़ी हैं। काबुल में तालिबानी शासन इस्लामाबाद को भारत के खिलाफ सामरिक पैठ और कश्मीर में जारी आतंकी संघर्ष में फायदा पहुंचाएगा। तालिबान की दुश्मनी से ज्यादा उसकी दोस्ती दिल्ली के लिए कहीं ज्यादा फायदेमंद है।

(लेखक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं)

response@jagran.com

नैतिक पतन का शिकार लोकतंत्र

एनके सिंह

अगर नेता, नौकरशाह और यहां तक कि जज भी नैतिकता के निचले पायदान पर दिख रहे हैं तो इससे गंभीर बात और कोई नहीं

देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सीबीआइ को इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज करने की इजाजत दे दी है। तमाम जांच-पड़ताल के बाद जज के प्राथमिक तौर पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के सुबूत मिले हैं। संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को नैतिकता की प्रतिमूर्ति मानते हुए उन्हें पद पर रहने के दौरान हर संवैधानिक सुरक्षा कवच से नवाजा था और उन्हें पद से हटाना एक जटिलतम प्रक्रिया यानी महाभियोग के तहत लगभग नामुमकिन कर दिया था। जिस प्रजातंत्र को उन्होंने इतनी कुर्बानियां देकर हासिल किया उसके भावी पतन का शायद उन्हें अंदाजा नहीं था। देश में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश पर पूरा प्रशासन 'कांवड़ियों' के आगे इतना नतमस्तक हो गया कि एक जिले के एसपी ने एक कांवड़िये का सार्वजानिक रूप से न केवल पैर दबाया, बल्कि उसका वीडियो आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड भी किया, ताकि मुख्यमंत्री देख सकें कि उनके आदेश का अमल किस शिद्दत से किया जाता है। एक अन्य जिले में डीएम और एसपी ने उन पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए और मीडिया को उसका वीडियो उपलब्ध कराया।

लौहपुरुष सरदार पटेल को इस 'स्टील फ्रेम' (वह ब्यूरोक्रेसी को फौलादी ढांचा कहते थे) पर इतना भरोसा था कि संविधान के अनुच्छेद-311 में अधिकारियों को दिए गए सुरक्षा कवच के पक्ष में उन्हें कहा था कि यह कवच इसलिए जरूरी है ताकि अधिकारी राजनीतिक आकाओं के सामने तन कर अपनी बात कह सकें और काम कर सकें। आज 70 साल बाद वह फौलादी ढांचा रीढ़विहीन दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश के ही उन्नाव जिले में सत्ताधारी दल का एक विधायक एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में साल भर से जेल में बंद है। कुछ दिन पहले जब परिवार के साथ वह पीड़िता एक गाड़ी में जा रही थी तो गलत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने जबरदस्त टक्कर मारी। उसके बाद से वह पीड़िता वेंटिलेटर पर है और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हैं, जबकी उसके दो रिश्तेदार मौके पर ही मर गए। पीड़िता की मां तथा चाचा के आरोप पर और पूरे राज्य में लोगों के जनाक्रोश को देखते हुए पुलिस ने विधायक पर हत्या का और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया। जाहिर है अगर आरोपी विधायक गवाहों को डराने-धमकाने के अंदेशे में जेल में नहीं रहता तो इन दिनों विधानसभा में कानून बना या बिगाड़ रहा होता।

एक अन्य मामले पर जरा नजर डालें। सिक्किम में जनता ने सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को बहुमत दिया और विधायकों के बहुमत ने, जिनमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, अपने नेता प्रेम सिंह तमांग को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि वह 2017 में भ्रष्टाचार के मामले में साल भर जेल की सजा काट चुके थे और चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो चुके थे। यहां सवाल है कि आखिर किसका विवेक गलत था, जनता का या विधायकों का? अब मुख्यमंत्री चुनाव आयोग से गुहार लगा रहे हैं कि कानून में प्रदत्त अधिकारों के तहत वह उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दे दे। भ्रष्टाचार में चार्जशीट के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव उस समय के कानून (अंतिम अदालत से सजा न मिलने तक अभियुक्त पाक-साफ माना जाता था) के मुताबिक वर्षों तक बिहार में सरकार बनाते रहे और संसद में मंत्री के रूप में कानून बनाते रहे। बिहार की जनता उन्हें वोट भी देती रही। सवाल है कि क्या 70 वर्षों में जनता का विवेक अपने प्रतिनिधियों को लेकर आज भी वही है या अच्छे नैतिक बल वाले लोग राजनीति में आ ही नहीं रहे हैं? आज जनता के सामने विकल्पहीनता की स्थिति आ गई है या फिर सत्ता के असर के चलते राजनीति अपना नैतिक प्रभाव खोती जा रही है?

आजादी के इतने वर्षों प्रजातंत्र के बाद अगर हमारे कुछ न्यायाधीश, जन-प्रतिनिधि और हमारी ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा भाग नैतिक पतन के सबसे निचले पायदान पर दिखाई देते हैं तो यह गंभीर चिंता की बात है। यह भी उतनी ही चिंता की बात है जब जनता भ्रष्टाचार की सजा काट रहे नेता वाली पार्टी को बहुमत दिलाकर और सत्ता में लाकर अपना भाग्यविधाता बनाती है और वह संविधान में निष्ठा की शपथ लेकर फिर वही सब कुछ करता है जो कानूनन जुर्म है।

1828 में अमेरिका में जैक्सोनियन युग के प्रजातंत्र की धूम थी। उसे समझने के लिए फ्रांस के राजनीतिक शास्त्र के जाने-माने विद्वान टोक्विल अमेरिका गए और उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि यह सबसे खराब प्रजातंत्र है जिसमें अल्पसंख्यक मत का न तो न्यायपालिका में, न ही विधायिका में और न ही किसी और जन विमर्श में कोई स्थान है। उन्होंने वापस लौटकर 'बहुसंख्यक का आतंक' शीर्षक से एक लेख लिखा जो भविष्य के प्रजातंत्र के लिए दिशा-निर्देशक बना। उसी तरह 1860 में ब्रिटेन में भी सबको मतदान का अधिकार संबंधी विवाद पर प्रजातंत्र में उदारवाद के जनक जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था, 'मैं इसका पक्षधर कभी नहीं हो सकता कि अंगूठाछाप आदमी को मतदान का अधिकार मिले।' इसके विपरीत भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने सार्वजानिक व्यस्क मताधिकार के पक्ष में संविधान बनाया, जबकि उस समय साक्षरता मात्र 12 प्रतिशत थी। आज साक्षरता 76 प्रतिशत है, लेकिन क्या इसके साथ लोगों की सोच, तर्क-शक्ति और सामूहिक समझ भी बदली है? क्या बेहतर शिक्षा, प्रति-व्यक्ति आय, सूचना के प्रवाह ने भारत के नागरिकों की नैतिक गुणवत्ता बदली है? अगर हां, तो जज भ्रष्टाचार का आरोपी क्यों है, विधायक दुष्कर्म और हत्या के आरोप के बाद भी अपनी पार्टी का सदस्य क्यों है? कैसे जनता एक साल जेल की सजा काट चुके एक नेता की पार्टी को सरकार बनाने के लिए चुन लेती है और कैसे वह नेता संविधान को ठेंगा दिखाते हुए मुख्यमंत्री बन जाता है? और अंत में कैसे फैलादी ढांचे की बुनियाद का कोई हिस्सा-आइएएस और आइपीएस रीढ़विहीन हो जाते हैं? शायद प्रजातंत्र में ही कहीं 'नैतिक लोचा' है।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मन का विज्ञान

मन मनुष्य के शरीर का अदृश्य अंग है जो दिखाई नहीं देता, किंतु वह शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मन के अंदर संपूर्ण दुनिया समाहित है। मन एक ऐसा पर्दा है जिस पर इच्छाएं प्रक्षेपित होती हैं। हमारे शरीर में इंद्रियां जो भी कार्य करती हैं वे मन के सहयोग से करती हैं। मन के बिना इंद्रियां ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकतीं। अतः मन को महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अक्सर कहा जाता है कि मन पर काबू पा लिया तो समझो जीवन को साध लिया।

भारतीय शास्त्रों में मन के लिए मनस् शब्द का प्रयोग किया गया है। जिसका अर्थ है वे साधन या उपक्रम जो किसी घटना, विचार या ज्ञान के लिए मुख्य रूप से जवाबदेह होते हैं। मन का महत्व इसलिए अधिक हो जाता है, क्योंकि यह ज्ञानेंद्रिय और आत्मा को परस्पर जोड़ने वाली कड़ी है। जिसकी सहायता से ज्ञान की प्राप्ति होती है। मन अपने आप में निर्जीव तत्व है। जब मन आत्मा के संसर्ग में आता है तभी इसमें अनुभूति होती है। प्रत्येक आत्मा के साथ एक मन जुड़ा हुआ होता है। जो उसका आंतरिक सहायक माना जाता है। इसलिए आयुर्वेद में मन को सत्व भी कहा गया है। जिस प्रकार ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्त करने का बाहरी साधन हैं उसी प्रकार मन ज्ञान प्राप्ति का आंतरिक साधन है।

कहावत है-मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अतः जब व्यक्ति अपने मन में यह सोच लेता है कि वह अमुक काम नहीं कर सकता तो वह अपने अंदर नकारात्मक गुण पैदा कर लेता है। और जब व्यक्ति यह सोच लेता है कि वह अमुक काम कर सकता है तो वह अपने अंदर सकारात्मक गुण पैदा कर लेता है। कबीरदास के अनुसार मन मूर्ख है, लोभी है, चंचल और चोर है। यदि मन बेलगाम हो जाए तो यह हमें विनाश के मार्ग पर ले जाता है। इसलिए मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। मन पर विचारों का प्रभाव होता है। अतः जैसे हमारे विचार होंगे वैसा ही हमारा मन भी होगा। मन भूमि में रोपे गए विचार नामक बीज की किस्म ही किसी के बुरे एवं अच्छे व्यक्तित्व का निर्धारण करती है।

देवेंद्रराज सुथार

फिटनेस पर बढ़ता जोर

अनीश कुमार

एक दशक पहले फिटनेस उत्पादों का घरेलू बाजार चार हजार करोड़ का था, जो अब 14 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है

हाल ही में एक तथ्य सामने आया है कि बीते दस वर्षों में देश में फिटनेस को लेकर जागरूकता काफी बढ़ गई है। इसके चलते फिटनेस उत्पादों का घरेलू बाजार लगभग चार गुणा बढ़ गया है। एक दशक पहले यह चार हजार करोड़ रुपये का था, जो अब 14 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। इसमें स्वदेशी उत्पादों का हिस्सा छह हजार करोड़ रुपये और चीन से आयतित उत्पादों का हिस्सा आठ हजार करोड़ रुपये है। बेहतर स्वास्थ्य को लेकर लोगों की सोच में जो बदलाव आया है, ये आंकड़े उसी की झलक पेश कर रहे हैं।

दरअसल आज आधुनिक जीवनशैली और खानपान जनित बीमारियां लोगों की चिंता का एक बड़ा कारण बनती जा रही हैं। हमने आधुनिक जीवनशैली के नाम पर ऐसी आदतों को अपना लिया है जिसने जाने अनजाने कई तरह की गंभीर बीमारियों को हमारे जीवन में जगह दे दी है। जीवन की आपाधापी में हम संतुलित भोजन नहीं ले पा रहे हैं। आहार में शक्कर और वसा की अधिक मात्रा भोजन को हानिकारक बनाती है। ऊपर से सुविधाएं बढ़ने से लोगों की शारीरिक गतिविधियां एकदम कम हो गई हैं जिससे अतिरिक्त कैलोरी शरीर में जमा होती जा रही है। इन सबके चलते विश्व के सबसे युवा देश भारत में आज बड़ी संख्या में युवक ह्रदय रोग, मधुमेह, तनाव, गठिया, दमा जैसी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ये बीमारियां सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं रही हैं, इनका विस्तार छोटे शहरों और गांवों तक तेजी से हुआ है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2020 तक भारत में सबसे अधिक मृत्यु ह्रदय संबंधी रोगों के कारण होगी। कुछ शोध बताते हैं कि आज की खराब जीवनशैली के कारण अगले करीब एक दशक में भारत की आबादी के लगभग बीस फीसद युवा ह्रदय संबंधी बीमारियों से ग्रस्त होंगे। रहन-सहन में आए इस बदलाव ने महिलाओं एवं पुरुषों के प्रजनन क्षमता को भी काफी प्रभावित किया है। आज करीब 15 फीसद महिलाएं बांझपन की समस्या से ग्रस्त हैं। पुरुषों में गंजे होने और महिलाओं में बाल गिरना भी कहीं न कहीं इसी की देन है। इससे शरीर में जरूरी प्रोटीन, विटामिन और खनिज पोषक तत्वों की कमी पड़ रही है। इसका प्रभाव हमारी उम्र पर भी पड़ रहा है।

युवावस्था न केवल खुद के विकास के लिए अहम होता है, बल्कि यही वह समय होता है जब कोई भी युवा खुद को परिवार, समाज और देश के लिए तैयार करता है। ऐसे में देश की एक बड़ी ऊर्जावान आबादी के स्वास्थ्य में इस तरह की गिरावट का आना निश्चित रूप से चिंताजनक है। इसलिए जीवनशैली और खानपान की आदतों की वजह से पैदा हो रही बीमारियों पर परिवार, समाज और सरकार के साथ हमें खुद भी ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि धीरे-धीरे लोग इसके प्रति जागरूक हो भी रहे हैं। और अपने को स्वस्थ रखने के लिए तमाम जतन कर रहे हैं जिसकी बानगी योग के बढ़ते चलन और फिटनेस उत्पादों की मांग में आई यह बढ़ोतरी है।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थी हैं)

शिक्षा का माध्यम बनें भारतीय भाषाएं

भारतीय भाषाओं के समक्ष बड़ी चुनौती शीर्षक से शंकर शरण द्वारा लिखित लेख पढ़ा। लेखक ने भाषाओं के संदर्भ में वर्तमान के अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया है। निःसंदेह आज भी ब्रिटिश शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर पूरी तरह हावी है और उसको हटाने को लेकर अथवा भारतीय भाषाओं की पुनर्स्थापना को लेकर सारा विमर्श राजनीतिक अधिक हो गया है। निश्चित रूप से लेखक द्वारा उठाया गया यह प्रश्न उचित है कि भाषा निर्जीव यंत्र नहीं है, क्योंकि भाषा ही वह माध्यम है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है और उसके अंदर चेतना का स्पंदन भी। यह भाषा ही सामाजिक-सांस्कृतिक सरोकारों को संजोती है तथा उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है। विश्व के अनेक देश ऐसे हैं जहां प्राथमिक ही नहीं, पूरी शिक्षा वहां की अपनी भाषा में दी जाती है और वे देश आज उच्च शिखरों को छू रहे हैं। फिर कौन-सी बाधा है कि हम अपनी भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम नहीं बना पा रहे हैं? आज यह एक गंभीर समस्या है कि हमारे अबोध बालक विदेशी भाषा के माध्यम से अपने ज्ञान का विकृत विस्तार कर रहे हैं और दादी-नानी के किस्से-कहानियों में छिपे संस्कारों से दूर हो रहे हैं। अंग्रेजी के वर्चस्व से आज हम सब ग्रसित हैं। आवश्यकता है मजबूती से निर्णय लेकर भारतीय भाषाओं में विमर्श की ओर बढ़ा जाए तथा शिक्षा और संस्कार की भाषा भारतीय भाषाएं हों ऐसा प्रयास किया जाए। हिंदी संपर्क की भाषा है, संविधान सम्मत राजभाषा भी है। क्या आज यह अनिवार्य नहीं है कि हम अंग्रेजी को छोड़कर, प्रादेशिक भेदभाव भूलकर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को पुनर्स्थापित करें?

डॉ. वेदप्रकाश, हंसराज कॉलेज, दिल्ली

मेलबाक्स

डैमेज कंट्रोल की कवायद

उन्नाव दुष्कर्म कांड में चौतरफा आलोचना झेलने के बाद आखिरकार भाजपा ने अपने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निकाल दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद बैक फुट पर आई भाजपा को ये कार्रवाई करनी पड़ी। पिछले एक साल में पीड़िता की मां ने उत्तर प्रदेश के पुलिस को 33 पत्र लिख कर सुरक्षा की मांगी की थी। पत्र में उन्होंने लिखा था कि विधायक के आदमी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। साफ है कि विधायक को सत्ता की शक्ति हासिल थी। अब तक पीड़िता के परिवार के कई सदस्य मारे जा चुके हैं। पीड़िता स्वयं अस्पताल में जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती करते हुए विधायक से जुड़े सभी केस दिल्ली ट्रांसफर कर दिए हैं। जांच भी उत्तर प्रदेश पुलिस से लेकर सीबीआइ को सौंपी जा चुकी है। देर से ही सही, भाजपा ने विधायक को पार्टी से बाहर तो किया, लेकिन ये पार्टी की संवेदनशीलता नहीं, सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है।

brijesh.srivastava31@yahoo.com

बड़ा सामाजिक बदलाव

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ राज्यसभा सदस्य गुलाम नबी आजादी का कहना है कि तीन तलाक विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने के बजाय रातों रात सदन की कार्यसूची में डाल कर पारित करा दिया गया। यह हास्यास्पद बयान लगता है। जिसका खंडन भाजपा द्वारा तुरंत किया गया। हालांकि कांग्रेस को समय रहते अपने सदस्यों को व्हिप जारी करना चाहिए था। वैसे भी राज्यसभा में तीन तलाक विधेयक पर सदन में छह घंटे बहस चली। कांग्रेस के वक्तव्य से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि राजनीतिक तौर पर मुस्लिम वोट बैंक के खातिर तीन तलाक विधेयक पास ना करवा कर और कोई ना कोई अड़ंगा लगाकर प्रवर समिति के पास भेजने की पक्षधर थी। सदन में 20 विपक्षी सांसदों की अनुपस्थिति ने तीन तलाक विधेयक को बिल बना कर इतिहास रचने के साथ बड़े सामाजिक बदलाव का रास्ता साफ कर दिया है। मुस्लिम महिला विवाह एक्ट का बन जाना राजनीतिक तौर पर कांग्रेस की जड़ों पर जबरदस्त प्रहार है। अब चाह कर भी विपक्षी पार्टियां इस बिल का विरोध नहीं कर सकतीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि केंद्र सरकार की जबरदस्त प्रबंधन कौशल की वजह से मुस्लिम महिला विवाह विधेयक को राज्यसभा से पारित करवाया गया जो तलाक-ए-बिद्दत पर फौरन नकेल कसेगा, क्योंकि ये आपराधिक श्रेणी का कानून है। मुस्लिम महिला अधिकारों की रक्षा भी करेगा।

दीपक गौतम, सोनीपत

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिएः नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।